

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक



वर्ष: 01

अंक: 01 देहरादून, शुक्रवार 10 अप्रैल 2026

मूल्य 2 रुपये

पृष्ठ: 8

www.aawamindia.com

धामी युग में उत्तराखण्ड : चुनौतियां अपार, निर्णय दमदार !

देहरादून : उत्तराखण्ड की राजनीति में “धामी युग” एक ऐसे दौर में शुरू हुआ जब 4 साल सबसे मजबूत बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी भाजपा के हाथ लगभग खाली थे। पुष्कर सिंह धामी ने जब सत्ता की कमान संभाली, तब राज्य कई मोर्चों पर जूझ रहा था। एक ओर राजनीतिक संकट सामने था त्रिवेन्द्र सिंह रावत को बदलना और फिर तीरथ सिंह रावत के बयानों में असहजता। भाजपा का दांव कारगर साबित नहीं हुआ था। दूसरी ओर देशभर में कोविड की दूसरी खतरनाक लहर थी। उत्तराखण्ड में भी कमोबेश वही हालात थे। भाजपा को देवभूमि उत्तराखण्ड में एक मजबूत, निर्णायक और स्थिर सरकार का संदेश देना था। ऐसे समय में पार्टी को पुष्कर सिंह धामी की याद आयी थी। क्रिकेट के खेल की तरह अंतिम ओवरों में आकर टीम को जिताने तक पुष्कर सिंह धामी उन चुनौतियों से पार हो गये। अब समय फिर लौटकर आया है। फिर चुनावी साल है, इस बार सरकार के हाथ खाली नहीं हैं। बड़े निर्णयों की लम्बी फेहरिस्त है लेकिन चुनौतियां अपार हैं क्या पुष्कर सिंह धामी एक फिर बड़ी और ऐतिहासिक पारी खेलने में कामयाब हो पायेंगे।

जुलाई 2021 उत्तराखण्ड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बड़े फैसले लिये। एक ओर जहां भाजपा ने प्रदेश की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंपी तो वहीं कांग्रेस भी गणेश गोदियाल को लेकर आयी। मुकाबला कड़ा होने लगा। पुष्कर सिंह धामी को उन 6 महीनों में ना सिर्फ खुद को साबित करना था बल्कि भाजपा की सरकार की वापसी के रास्ते भी बनाने थे। वहां से एक सौम्य छवि के साथ-साथ निर्णायक और कड़े फैसले लेने का सफर शुरू हुआ। उन दिनों अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म बहुत चर्चाओं में थी। “पुष्पा सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं फायर हैं मैं!” यहीं डॉयलाग उन दिनों खासा चर्चा में आया जब मंच से राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और कहा पुष्कर सिंह धामी फ्लावर भी हैं और फायर भी। भाजपा की गिरती हुई साख प्रदेश में

लौटने लगी। प्रदेश भाजपा के प्रचार ‘मोदी-धामी की सरकार’ को जनता ने स्वीकार किया। भाजपा पूर्ण और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गयी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खुद

लेकिन ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि यूसीसी को पुष्कर सिंह धामी की निर्णायक छवि के तौर पर याद रखा जायेगा।

इस मौजूदा कार्यकाल में सरकार 10



चुनाव हार गये पर चुनाव धामी के चेहरे और उनके वादों पर लड़ा गया था, भाजपा ने उनका सम्मान रखा और हारने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया।

पुष्कर सिंह धामी सरकार 2.0 शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश में यूसीसी लागू किया जायेगा। सरकार बनाने के बाद धामी अपना वादा नहीं भूले और यूसीसी लागू करने के लिए कदम बढ़ा दिये। लम्बी कानूनी प्रक्रिया के बाद 27 जनवरी 2025 को आखिरकार प्रदेश में यूसीसी अधिकारिक तौर पर लागू हो गया है और देशभर में उत्तराखण्ड एक नजीर बन गया। भाजपा के मुताबिक सामाजिक समानता और समरसता की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है

फरवरी 2023 से लागू देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून को अपनी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। नकल विरोधी कानून जैसे सख्त प्रावधानों से युवा वर्ग में धामी सरकार ने ये संदेश दिया था कि सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना चाहती है। ये निर्णय उन वर्षों की पीढ़ा का उत्तर हो सकता है जब एक युवा अपने जीवनभर की पूंजी और संघर्ष एक पेपर में झोक देता है और पेपर लीक हो जाता है। वो हाथ खाली रह जाते हैं जो असली हकदार होते हैं। धामी सरकार 2.0 शुरू होने के बाद भर्ती घोटाले में बड़े सिंडिकेट के नाम सामने आये। कई राजनीतिक लोगों के करीबी घरे में थे। युवा सड़कों पर थे। सरकार को स्पष्ट और कड़ा संदेश देना था तब ये सख्त कानून पारित हुआ। उन बड़ी मछलियों

को सलाखों के पीछे भेजा गया। हालांकि नकल समाज का वो पाप है जो इतनी सख्ती के बाद भी मिट नहीं पाया। कानून लागू होने के बाद भी पेपर लीक हुआ। युवा वर्ग एक बार फिर सड़कों पर उतरा और सीबीआई की जांच पर अड़ा रहा और सरकार ने भी युवाओं की बात का मान रखा। प्रदेश में पहली बार पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की गई।

धामी युग में औद्योगिक निवेश को भी सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है। प्रदेश में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार का मानना है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पास हुए हैं और 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रदेश में ग्राउंडिंग हो चुकी है। सरकार ने प्रदेश नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया और 25 से ज्यादा क्षेत्रों में निवेश के द्वार खोले। इसका असर धरातल पर भले ही थोड़ा धीमा हो लेकिन ये आंकड़े उत्तराखण्ड की आर्थिकी के लिए सुखद अहसास कराते हैं। उत्तराखण्ड सीमित संसाधन वाला एक हिमालयी राज्य है। आर्थिकी के अवसर तो बढ़ाने ही होंगे।

धामी सरकार ने अवैध अतिक्रमण और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी सख्ती दिखाई है। स्वयं मुख्यमंत्री अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि नीली-पीली चादरें डालकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने देंगे। मद्रसा बोर्ड पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। डेमोग्राफी पर मुख्यमंत्री स्वयं कई मंचों से खुलकर बोल चुके हैं।

पुष्कर सिंह धामी का केंद्रिय हाईकमान के साथ अच्छा तालमेल उनकी राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मीय भाव के साथ पुष्कर सिंह धामी से मिलते हैं वो शायद ही किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या अन्य नेता के साथ मिलते हो। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव है लेकिन ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के चहेते हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं अमित शाह

और राजनाथ सिंह भी पुष्कर सिंह धामी से विशेष लगाव रखते हैं। हाल ही में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी आत्मियता और मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। अमित शाह ने हरिद्वार में चुनावी जनसभा में उनके कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की है। राजनाथ सिंह ने उनके एक नई उपाधि ‘धुरंधर धामी की’ दी है। कुछ दिनों पूर्व ही में जेपी नड्डा भी उत्तराखण्ड आये तो जमकर धामी सरकार की तारीफ की। अब जब-जब प्रदेश में अटकलों का दौर शुरू होता है तो उतनी ही ताकत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि उभरती है।

ये बड़ी वजह है कि भाजपा हाईकमान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है। केंद्रिय हाईकमान उनके निर्णयों के साथ खड़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। प्रदेश को 5 नये कैबिनेट मंत्री मिले हैं। देर से ही सही मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार को बैलेंस कर लिया है। इतने लम्बे समय से इतनी छोटी कैबिनेट चलाना शायद ही कोई ओर कर पाता।

उत्तराखण्ड की शुरुआत से ही राजनीति मूलतः द्विध्रुवीय रही है। एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। लेकिन 2022 में पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पहली बार ये मिथक भी टूटा है। 2022 में कांग्रेस सरकार नहीं बना पायी और भाजपा को अब लगातार 10 वर्ष हो जायेंगे। अब भाजपा कांग्रेस के मुकाबले संगठन, संसाधन और नेतृत्व के स्तर पर आगे निकली है। कांग्रेस ने 2022 की हार के बाद गणेश गोदियाल से इस्तिफा ले लिया था जबकि उनका एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। गढ़वाल से किसी भी नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी। हालांकि अब चौथे वर्ष में गणेश गोदियाल को दुबारा लाया गया है और पीसीसी सौंपी गई है। प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस फिर वही पुराना मुकाबला लड़ने के लिए बेताब है।

(शेष पृष्ठ दो पर)

चारधाम यात्रा : शासन-प्रशासन ने कसी कमर, सीएम ने दिया सुरक्षित यात्रा का संदेश

देहरादून। सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और अफसरों को बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यात्रा राज्य की लाइफ लाइन है, जिसे व्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा में विशेषकर हेली सेवाओं में व्यावसायिक दृष्टिकोण की अपेक्षा मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सीएम ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी।

सरकार का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाना है जिसके सरकार



गंभीरता दिखायी है। मुख्यमंत्री ने सख्त



ने सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। सीसीटीवी और एआई आधारित निगरानी से यात्रा को हाईटेक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर बीते वर्ष शुरू की गई ग्रीन व क्लीन चारधाम यात्रा की मुहिम को इस बार और अधिक प्रभावी रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए सीएम ने प्लास्टिक मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों पर पर्याप्त संख्या में कलेक्शन बॉक्स लगाने और प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देश दिए कि हेलिकॉप्टरों की नियमित फिटनेस जांच अनिवार्य तौर पर की जाए। ऑपरेशनल ओवर लोडिंग से बचने के लिए समय-समय पर इन सेवाओं को विश्राम दिया जाए और एसओपी का पूरी सख्ती से पालन किया जाए। सीएम ने मौसम आधारित जानकारी व निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी स्पष्ट किया कि यात्रा मार्ग पर गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों को

जिम्मेदारी सौंपी कर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। साथ ही यात्रा मार्गों पर मेडिकल यूनिट के साथ ही अस्थायी अस्पताल स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिये कि धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए स्लॉट प्रबंधन व भीड़ नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए और ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

कानून-व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए सीएम ने कहा कि मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजारों में पुलिस व होमगार्ड की पर्याप्त तैनाती करें। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जाम की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न न हो और इसके लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की पहचान और संचालन किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की



देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्थापित परीक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर उन्हें उचित सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाए साथ ही इन केंद्रों पर स्थित एम्बुलेंस की फिटनेस का भी परीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने चारधाम कंट्रोल रूम पर ईसीजी की व्यवस्था हेतु पोर्टेबल मशीनों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि इस चारधाम यात्रा से हम श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ स्थित हॉस्पिटल का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री ने जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये साथ ही सीएमओ को एलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने के निर्देश दिये।

मंत्री ने जिलेवार स्वास्थ्य उपकरणों की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी जिलों के सीएमओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सफाई के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। किसी भी तरह की कमी पायी जाने पर सीएमओ की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल को रेफरल अस्पताल का तगमा खत्म करना होगा।

इस संबंध में भी कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। मंत्री ने जनपदवार विशेषज्ञ डॉक्टरों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मशीनों का सदुपयोग हो तथा सरकारी पैसे के दुरुपयोग न हो इसके लिए भी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता मरीज का सम्पूर्ण इलाज करना है। उन्होंने सभी डॉक्टरों को बेहतर कार्य कर उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।

इस अवसर पर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव कुर्वे, महानिदेशक सुनीता टट्टा, एमडी मनोज गोयल, निदेशक शिखा जंगपांगी तथा सभी जिलों के सीएमओ एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पृष्ठ 1 का शेष

धामी युग में उत्तराखण्ड.....

धामी सरकार के सामने अब चुनौतियां बदल चुकी हैं। विपक्ष ने एक दो मामलों पर सरकार को असहज करने का कार्य किया। अंकिता भण्डारी हत्याकांड उनमें से एक है। अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने तत्परता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और कोर्ट ने उन्हें सजा भी दे दी थी। किसी हद तक मामला शांत हो गया था। फिर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के बयानों से सवालिया निशान खड़े हो गये। कथित वीआईपी पर प्रदेश भर में सड़कों पर लोग उतरे। हंगामे हुए। भाजपा सरकार की ओर से सुबोध उनियाल और संगठन की ओर से नरेश बंसल ने मोर्चा संभालना चाहा। यहां तक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री अंकिता के मां-बाप से मिले और उनकी मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। ये बड़ा फैसला था। कुछ महीनों में ही दो मामलों पर राज्य सरकार सीबीआई तक पहुंची

थी। पेपर लीक के बाद अंकिता भण्डारी मामले में सीबीआई जांच चल रही है। राजनीतिक दबाव से इतर देखे तो पुष्कर धामी सरकार ने जन भावनाओं का मान रखा और इस चुनौती को किसी हद तक पार कर लिया।

अभी तक पुष्कर सिंह धामी की छवि मैनेजमेंट मोड से ज्यादा डिजीजन मोड की रही है। ये छवि ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन पर चुनौतियां ही नहीं जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ी है। क्योंकि उत्तराखंड केवल हिमालयी राज्य नहीं है, यह भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक चेतना का एक संवेदनशील क्षेत्र है। देवभूमि उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। लोगों ने अपनी जान दी है। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो यूपी में रहते हुए अधूरे थे। अब 25 वर्षों के बाद भी यदि वो सपने, सपने ही रहे तो मन का व्याकुल होना लाजिमी है। एक अस्थिर राजनीति वाले प्रदेश उत्तराखंड जहां मुख्यमंत्री बदलना आम बात है वहां पिछले कुछ सालों से

थोड़ी सी स्थिरता देखी गयी है। पुष्कर सिंह धामी इस जुलाई अपने 5 वर्ष पूरे कर लेंगे। सरकार को डबल इंजन के तौर पर केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूर्ण और स्पष्ट बहुमत की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, एक विजन रखते हैं, संवेदनशील हैं। धामी सरकार के सामने संभावनायें कम नहीं हैं। हालांकि सरकार ने उन संभावनाओं को किसी हद तक साकार भी किया है। पहली बार किसी सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद पर जोर दिया है। पर्यावरण और विकास के बीच तालमेल बनाया जा रहा है। सरकार जिस तरह से बिना किसी विरोध के निर्णय ले रही है तो शायद ये बेस्ट टाइम है जब उत्तराखंड के विकास की परिभाषा ही कुछ और होगी। सरकार ने युवाओं और महिलाओं पर जिस तरह फोकस किया है और इस प्रयास को थोड़ा और बढ़ाया जाये तो शायद पहाड़ की संरचना का मूल्य साकार हो सकता है।

नई डीएसी के आधार पर ही उपलब्ध कराया जाएगा सिलेंडर



चम्पावत। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं को मार्च माह में डीएसी होने के बावजूद गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं हो सका, उन्हें अब अप्रैल माह में नई डीएसी के आधार (जो स्वतः जनरेट होगा) पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस हेतु जिन उपभोक्ताओं ने अप्रैल माह में पूर्व में बुकिंग कराई है, उनकी डीएसी स्वतः

(ऑटोमैटिक) पुनः जनरेट हो रही है, इसके लिए उन्हें अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की नई डीएसी जनरेट नहीं हो रही है, तो वह संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।

14 अप्रैल को देहरादून आ रहे हैं पीएम मोदी, जनता को समर्पित करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून में आ रहे हैं और एशिया का सबसे लंबा ग्रीन कारिडोर (गणेशपुर से डाटकाली मंदिर तक 12 किमी) जनता को समर्पित कर दिया जायेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस अहम दौरे का प्रदेशवासियों को लम्बा इंतजार था। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद दिल्ली और देहरादून की दूरी महज ढाई घंटे रह

हेलीकॉप्टर से गणेशपुर (सहारनपुर) में उतरेंगे और फिर एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करते हुए कार से आईएसबीटी, जीएमएस रोड और कैनाल रोड होते हुए गढ़ी कैंट देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी महिंद्रा ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर डाटकाली मंदिर में हलचल

ये मान्यता है कि देहरादून व आसपास के क्षेत्रों जब भी किसी घर में नया वाहन आता है तो यहां वाहन पूजा के लिए जरूर आते हैं। इस मंदिर में अखंड ज्योत जलती है और यहां का प्रसाद लोग विदेशों तक लेकर जाते हैं। देहरादून में ये मान्यता है कि अंग्रेज जब दूनघाटी में आ रहे थे तो यहां प्रवेश के लिए उन्हें सुरंग बनानी थी। अंग्रेजों ने सुरंग का कार्य करना शुरू किया, पर लगातार काम में अड़चन आ रही थी। कहा जाता है कि एक दिन अंग्रेज इंजीनियर कर्नल कैटवे को सपने में माता के दर्शन दिए और मंदिर बनाने को कहा। इसके बाद 1936 में उन्होंने यहां मंदिर बनाया गया और मां काली की प्रतिमा स्थापित की गयी। इसके बाद सुरंग आसानी से बन गयी जो अभी तक मौजूद है। हालांकि अब वाहन नयी सुरंग से गुजरते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद सफर बहुत आसान होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ ढाई घंटे में दिल्ली पहुंचने का मार्ग ही नहीं, बल्कि दिल्ली और देहरादून के निकट स्थित कई शहरों में पहुंचने का पूरा रोड नेटवर्क स्थापित हो जायेगा। करीब 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दो प्रमुख एक्सप्रेसवे, साथ ही पांच नेशनल हाईवे और 10 से ज्यादा स्टेट हाईवे से कनेक्ट होकर पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी का जाल फैला देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली-बागपत मार्ग, मेरठ-बागपत मार्ग,

मेरठ-बुलंदशहर मार्ग, मुजफ्फरनगर-देवबंद-सहारनपुर मार्ग और मुजफ्फरनगर-शामली मार्ग प्रमुख हैं। अब यात्री दिल्ली में अक्षरधाम से चलकर आसपास के सभी "हॉट" में आसानी से जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी देहरादून के आसपास स्थित देहरादून-मसूरी, देहरादून-ऋषिकेश और देहरादून-विकासनगर मार्ग से कनेक्टिविटी

ये कोरिडोर दिल्ली-देहरादून के बीच दूरी कम करने के साथ ही सफर को सुगम बना रहा, बल्कि उत्तराखंड की सीमा में गणेशपुर से डाटकाली तक बना एशिया के सबसे बड़े ग्रीन कारिडोर के रूप में भी पहचान बना चुका है। सरकार ने इस तरह ग्रीन कोरिडोर का निर्माण किया है जिससे राजाजी टाइगर रिजर्व और



जायेगी।

यह जानकारी मिल रही है कि 13 अप्रैल से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में डाटकाली मंदिर से ही एलिवेटेड रोड को बंद कर दिया जायेगा। पीएम मोदी की जनसभा होने तक पुराने मार्ग से गाड़ियां निकाली जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काफिला आगामी 14 अप्रैल को शहर के अंदरूनी हिस्से में 14.1 किलोमीटर का सफर तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी

बढ़ गई है। यूपी की पुलिस लगातार पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी मंदिर में मां डाटकाली के दर्शन भी करेंगे। डाटकाली मंदिर देहरादून से सहारनपुर रोड पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा माता सती के नौ शक्तिपीठों में एक मनोकामना सिद्धपीठ है। देश-दुनिया से लाखों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं।



मिलने से पर्यटन स्थलों तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं अब सोनीपत, पानीपत, कुंडली, मानेसर, गुरुग्राम, पलवल, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, अंबाला और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा तक के पर्यटक देहरादून आसानी से पहुंच सकते हैं।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किमी के ग्रीन कोरिडोर की अपनी खासियत है।

शिवालिक रेंज के वन्यजीवों की आवाजाही में कोई खलल न पड़े। 18 प्रजाति के वन्यजीव नीचे से आसानीपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। किसी भी तरह के वाहनों के शोर के कारण वन्यजीव बिदकें नहीं, क्योंकि एलिवेटेड रोड पर साउंड बैरियर लगाए गए हैं। यही नहीं, ऐसी लाइट भी लगाई गई हैं, जिनकी रोशनी वन्यजीवों को परेशान न करे।

इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना पर समीक्षा बैठक हरिद्वार को मिलने जा रहा है आधुनिक रोपवे सिस्टम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में हरिद्वार को आधुनिक रोपवे सिस्टम मिलने जा रहा है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को राज्य सचिवालय में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा हरिद्वार शहर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन, लागत, भूमि हस्तांतरण, कन्सेशन अवधि और वित्तीय व्यवहार्यता समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव आवास ने अधिकारियों को परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।

बैठक के दौरान उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार मिश्रा ने हरिद्वार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का क्रियान्वयन और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी

(पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत डीबीएफओटी आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण में परियोजना

यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध



की संरचना, संभावित मार्ग, निर्माण कार्य और संचालन व्यवस्था की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से हरिद्वार शहर में

कराने में मदद मिलेगी।

समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने परियोजना की प्रति किलोमीटर लागत के संबंध में

विस्तृत जानकारी ली। इस पर प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि रोपवे स्टेशन, कार्यशाला और भूमि तथा अन्य आवश्यक क्लियरेंस को छोड़कर परियोजना की संरचना के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग 75 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह लागत केवल निर्माण कार्य से संबंधित है, जबकि भूमि, स्टेशन निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं अलग से शामिल होंगी। बैठक में परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में रोपवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है, वह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। इस पर सचिव आवास ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड

शासन के सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को पुनः पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस विषय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है, इसलिए अब अनुस्मारक पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव सिंचाई, उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रस्तावित भूमि को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 99 वर्षों की लीज पर आवास विभाग, उत्तराखंड शासन को हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

समीक्षा के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को डीपीआर स्तर पर अनुमोदित करते हुए इसे आगे की कार्यवाही के लिए ईएफसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के सभी तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

सम्पादकीय

प्रथम संस्करण : नई दिशा और जनविश्वास का आईना



प्रथम संस्करण अखबार के आगामी भविष्य का आईना होता है। यह एक असीम यात्रा की शुरूआत का वो पहला कदम होता है जो उर्जा, उद्देश्य, साहस और जिम्मेदारी का अहसास कराता है। प्रथम संस्करण ही तय करता है कि हमारी दिशा क्या होगी और हमारा रास्ता क्या होगा। आवाम इंडिया भी आज प्रथम संस्करण के माध्यम से समाज, लोकतंत्र और आम जन की आवाज को मजबूती देने के संकल्प के साथ पाठकों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। आवाम इंडिया की शुरूआत पर हम जिम्मेदारी के साथ ये भरोसा दिलाते हैं कि हम केवल एक अखबार का प्रकाशन नहीं, बल्कि सत्य, साहस और सरोकारों की उस यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक, सशक्त और एकजुट बनाना है।

दरअसल पत्रकारिता एक बड़ी जिम्मेदारी है और अखबार उस जिम्मेदारी का शुरूआत से ही ध्वजावाहक रहा है। अखबार आज भी करोड़ों लोगों की संवेदनाओं, विचारों और सपनों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। खबरों की अंधाधुंध दौड़ में जब भ्रम और सत्य के बीच तुलना की जाती है जो आज भी लोग अखबार को विश्वास की नजर से देखते हैं और पढ़ते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसी विश्वास को बनाये रखे। आवाम इंडिया कागज पर काली स्याही से छपी खबरों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और सच के प्रति हमारे साहस की घोषणा का प्रतीक होगा। हमारे प्रत्येक पाठक को पन्ने पलटते हुए हर खबर निष्पक्ष प्रतीत हो, हर खबर जन सरोकार से जुड़ी हुई लगे ये हमारा उद्देश्य है। हमें आम आदमी की आवाज बनना है। गाँव से लेकर शहर तक, किसान से लेकर युवा तक, महिलाओं से लेकर श्रमिक वर्ग तक, सबकी समस्याओं, उपलब्धियों और उम्मीदों को ईमानदारी से आप के बीच लाना है।

आवाम इंडिया ने अपने पहले संस्करण में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचारों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों को विशेष स्थान दिया है। हमारा प्रयास है कि खबरें केवल सनसनी न बनें, बल्कि समाधान और निष्कर्ष का हिस्सा बनें। हर पन्ना, हर खबर विचार, विमर्ष और जनसंवाद को प्रोत्साहित करे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का काम करे। आवाम इंडिया ने पत्रकारिता के लिए पावन भूमि उत्तराखंड और हिंदी भाषा को चुना है। हमें दोनों पर गर्व है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अहसास है। हजारों साल की सभ्यता, संस्कृति और परम्पराओं का प्रतीक है। देश का शीष है, देश का मान है। जबकि हिंदी भारत की आत्मा है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास संघर्ष, त्याग और साहस से भरा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी अखबारों ने जन-जागरण की ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों को चुनौती दी, बल्कि आम जनता में स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी प्रज्वलित किया। आज, दशकों बाद भी पत्रकारिता में परिस्थितियाँ बदली हैं। विश्वास पहले से कम हो सकता है लेकिन विश्वास है।

ये डिजिटल युग का दौर है। सूचनाओं की भरमार है। पेंडुलम के दो छोर की तरह सकारात्मक और नकारात्मक खबरों का बोलबाला है। हर पल खबरें बदल रही हैं। सच और झूठ का फर्क पहचानना आसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते खबरों के नाम पर क्या परोसा जा रहा है ये पाठक भली-भाँति जानते हैं। ऐसे दौर में अखबार अपनी विश्वसनीयता को किसी हद तक बचाये रखे हैं ये बड़ी बात है। हमारा भी यही दायित्व है कि पत्रकारिता के मूल स्तंभ सत्य, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ समझौता ना हो।

हम आवाम इंडिया अपने पाठकों, संवाददाताओं, लेखकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके विश्वास और सहयोग से यह पहला संस्करण संभव हो पाया है। हम आपकी प्रेरणा पर इस यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस यात्रा के हमेशा सहभागी रहेंगे। यह अखबार तभी सफल होगा जब पाठक इसे अपना समझेंगे, इसकी कमियों पर सुझाव देंगे और इसकी मजबूती में सहभागी बनेंगे।

मौ. वसी जैदी
सम्पादक

ईरान की सैद्धान्तिक जीत के मायने

सौलत जबी, वरिष्ठ पत्रकार

7 अप्रैल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि आज रात एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जायेगी जो दुबारा वापिस नहीं लायी जा सकेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो लेकिन शायद ऐसा ही होगा। 28 फरवरी से शुरू होकर लगभग 40



दिन चले इस ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में ये सबसे बड़ी और अंतिम धमकी थी। दुनियाभर की निगाहें अमेरिका के कदम पर थी। लोग प्रार्थना करने लगे। सड़कों पर उतर गये, टीवी से चिपक गये। हर कोई बेताब था कि शायद एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। एशिया में रात गहराने लगी। अचानक पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में आता है और डोनाल्ड ट्रंप हर शर्त पर सहमत होते चले जाते हैं। 14 दिन का सीजफायर घोषित हो जाता है और ईरान को बहुत कुछ गंवाने के बाद भी एक सैद्धान्तिक जीत हासिल हो जाती है। ईरान की अडिगता और हिम्मत हठधर्मी डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। युद्ध होता है तो ईरान की हिम्मत पर और युद्ध रूकता है तो ईरान की शर्तों पर। ना होमूज पर ईरान का कंट्रोल कम हुआ और ना ही अमेरिका के मुताबिक सत्ता परिवर्तन हो सका। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से ईरान को समझने में कहां चूक हो गयी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तय समय से कुछ वक्त पहले ट्रंप ईरान की शर्तें मान लेते हैं।

28 फरवरी की सुबह अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, उस ऑपरेशन के शुरूआती दौर में ही ईरान ने अपना सर्वोच्च लीडर खो दिया। दुनियाभर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब ईरान मैदान में टिक सकता है। व्हाइट हाउस को तो यकीन था कि बहुत जल्द उनके हक में फैसला होगा जो वेनेजुएला जैसा तेज, साफ और निर्णायक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साहित थे कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन 40 दिन तक हजारों हमले झेलने के बाद भी ईरान झुका नहीं। वो तस्वीर जो व्हाइट हाउस देखना चाहता था वो नजर नहीं आई। बल्कि होमूज और गले की फांस बन गया। अमेरिका डबल फंस गया। एक ओर अपनी आवाज



डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गयी दूसरी ओर मित्र देशों ने भी हाथ खींच लिये। इजराइल अमेरिका की ओर देखना लगा और अमेरिका अब क्या करें और कैसे करे इस खींचतान में उलझ गया। ईरान को जितना डराने की कोशिश की जाती, ईरान उतनी ही हिम्मत दिखाता। ये एक अंतहीन युद्ध की भयानक शुरूआत जैसा हो गया। अमेरिकी सेना को एक बेवजह के युद्ध में ढकेलने जैसा था जिसका नतीजा किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हो सकता था। आखिरकार वह हुआ, जो किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ने सभ्यता को मिटाने की धमकी वापस ली और 14 दिन का संघर्षविराम स्वीकार कर लिया। इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ लेकिन हिम्मत और जज्बे की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। इस जंग के बाद भी ईरान ने लेबनान को अकेला नहीं छोड़ा और इजराइल को भी सीजफायर करना पड़ा। इस युद्धविराम की सबसे बड़ी होमूज ही रहा है। होमूज में ईरानी गतिरोध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। खाड़ी के कई देश अमेरिका के इस युद्ध में फंस गये थे। ट्रंप के सामने दो ही रास्ते थे। या तो ईरान की शर्तों को माना जाये या ईरान के उस 600 किमी हिस्से पर कंट्रोल किया जाये जहाँ से होमूज के रास्ते खुले। अमेरिकी सेना होमूज जलडमरूमध्य पर जल्दी नियंत्रण नहीं कर सकती थी, इसे कंट्रोल में करने और फिर उस कंट्रोल को बनाये रखने में दशक बीत जाते। अमेरिका के लिए ये आसान नहीं था। अमेरिका इज्जत के साथ मध्यस्थता के रास्ते तलाशने लगा। ऐसे में वो सभ्यता मिटाने वाला ट्वीट और फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता ये रास्ता प्लान किया गया होगा और इस तरह अमेरिका किसी तरह इस झंझट से बाहर निकल पाया।

इस युद्ध में ईरान ने अपनी ताकत खूब

दिखायी। ईरान ने ये साबित किया कि वह हजारों हमले झेलकर भी एक असरदार युद्ध लड़ सकता है। दुनियाभर की तेल आपूर्ति बाधित कर सकता है और अमेरिका जैसे ताकतवर को झुका सकता है। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी। लोग इस इंतजार में रहे कि ये मिसाइलें कितनी तादाद में हैं और कब खत्म होगी पर हफ्तों की बमबारी के बाद भी उसकी मिसाइल क्षमता मजबूत रही। ईरान ने जेट सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो रडार को भी चकमा दे सकता है।

अब ईरान ने अपनी शर्तों में सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। होमूज जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा जारी रखने का बात कही है। ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले पूर्ण रूप से बंद करने की भी मांग की है और इन सभी शर्तों को अमेरिका को मानना पड़ा है।

अब दो हफ्ते के संघर्षविराम की योजना के बाद ईरान और ओमान को होमूज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान शुल्क वसूल सकता है और शायद इसी पैसे से ईरान पुनर्निर्माण की शुरूआत करेगा। होमूज ओमान और ईरान दोनों के समुद्री क्षेत्र में है। यानि ईरान का दबदबा इस जलमार्ग पर कायम रहेगा। इस युद्ध रूकने के बाद तेल की कीमतें फिलहाल थोड़ी सी गिरी हैं लेकिन बहुत कुछ आगामी शांति वार्ता पर निर्भर करेगा। इस युद्ध ने दुनियाभर की इकोनोमी को प्रभावित किया है। ईरान का बिखरा हुआ शासन आने वाले समय में और मजबूत होगा और वो अमेरिका के सामने अब ज्यादा अड़ियल साबित होगा। इस पूरे युद्ध में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और अन्य खाड़ी मुस्लिम देशों को बड़ा नुकसान हुआ। उनकी आवाम उनसे नाराज रही और अमेरिका से भी क्या हासिल हुआ।

खाद्य नागरिक आपूर्ति की प्रवर्तन टीमों ने किया औचक निरीक्षण

पौड़ी। जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन पर खाद्य नागरिक आपूर्ति की प्रवर्तन टीमों द्वारा विभिन्न

स्थानों पर संचालित गैस एजेंसियों, प्रतिष्ठानों, होटल-ढाबों तथा पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि बुधवार को जनपद में कुल 24 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें

से श्रीनगर क्षेत्र में 02 गैस गोदाम, कोटद्वार में 01 गैस गोदाम व 04 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, पौड़ी व पाबौ क्षेत्र में 01-01 गैस गोदामों का तथा नौगांवखाल/पोखड़ा क्षेत्रों में 15 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटेर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राह्मणवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,

समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331

हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।

facebook: www.facebook.com/indiaaawam,
X: www.x.com/aawamindia,

youtube: www.youtube.com/@aawamindia,
Instagram: <https://instagram.com/aawamindia>

राजनीतिक अवकाश बनाम सक्रियता कितने जरूरी है कांग्रेस के लिए हरीश रावत!

इन दिनों पूरे प्रदेश में हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश की चर्चा है। अपने 60 साल की राजनीतिक यात्रा में हरीश रावत ने 15 दिन का पहला अवकाश मांगा है और इस बीच सभी राजनीतिक

स्थापित हो गये। उस समय एक बार ही नहीं लगातार तीन बार वो अल्मोड़ा से लोकसभा चुनाव जीते जिसमें से दो बार मुरली मनोहर जोशी को हार का सामना करना पड़ा और एक बार 1989 में काशी

बात को मनाने का हुनर जानते हैं। 2007 में एनडी तिवारी सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा गया लेकिन एनडी तिवारी का अलविदा साथियों बयान देशभर में चर्चाओं में रहा। कांग्रेस महज 23 सीटों पर सिमट गयी। 2012 में कांग्रेस को फिर सरकार बनाने का मौका मिला और इस बार विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। हरीश रावत ने पार्टी फोरम पर विरोध किया लेकिन अपनी उपयोगिता बनाये रखी और पार्टी ने उन्हें मनमोहन

बहुत करीब से लौटकर कांग्रेस महज 19 सीटों पर सिमट गयी। अब फिर रामनगर

उस दिन को कांग्रेस को याद रखते रहना चाहिए। उनके मुताबिक वो सिर्फ हरीश



शांत मन से अपने सार्वजनिक जीवन के 60 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर बहुत कुछ मनन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इन 60 वर्षों की अथक यात्रा के बाद मुझे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अर्जित अवकाश लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है और मैं अर्जित अवकाश की पहली किश्त के रूप में 15 दिन तक राजनीतिक सोच व राजनीतिक कार्यों से व्रत रहूंगा। हाँ, इस दौरान मंदिरों में पूजा-अर्चना, कुछ ईद मिलन व मांगलिक समारोह में अवश्य भाग लूंगा और इन 15 दिनों में मैं अपनी जीवन यात्रा के उन प्रसंगों और मोड़ों को उकेरने की कोशिश करूंगा, जो समय के साथ बहुत नीचे कहीं चले गए हैं।

**हरीश रावत
पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखंड**

सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया। 2014 में आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। यहां से हरीश रावत एक बार फिर केंद्र विंदु बन गये।

2016 में कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो गई। विजय बहुगुणा अपने साथियों के साथ कांग्रेस से अलग हो गये और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हरीश रावत ने इस दौरान कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संघर्ष किया। कोर्ट में लड़ाई, फ्लोर टेस्ट और फिर सत्ता में वापसी, यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। हालांकि 2017 में उनकी सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। भाजपा ने बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनायी। हरीश रावत दो सीटों पर चुनाव हारे। ये हार आसान नहीं थी। हरीश रावत इस हार से भी नहीं टूटे और सक्रिय राजनीति करते रहे। 2019 में वो नैनीताल से लोकसभा चुनाव हार गये। 2022 में कांग्रेस ने मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। ये चुनाव भले ही सामूहिक नेतृत्व में था लेकिन हरीश रावत ही मुख्य बिंदु थे। यहां से वो रामनगर सीट चर्चा का विषय बनी।

2022 में पहले हरीश रावत को रामनगर से प्रत्याशी बनाया गया लेकिन रणजीत रावत के अंदरूनी विरोध के चलते पार्टी उन्हें लाल कुआं ले गयी। इस बदलाव का कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस लालकुआं, सल्ट और रामनगर तीनों सीटें हार गयी। सिर्फ ये सीटें ही नहीं सत्ता के



सीट चर्चाओं में हैं। रणजीत रावत पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो 5 साल से तैयारी में थे लेकिन वापिस सल्ट लौटना पड़ा था। संजय नेगी की पत्नी रामनगर से ब्लॉक प्रमुख हैं और कोई दो राय नहीं है कि संजय नेगी भी रामनगर से बड़ा नाम हैं। इस मौन के पीछे हरीश रावत की ये इच्छा हो सकती है कि संजय नेगी को पार्टी में शामिल करके रामनगर से प्रत्याशी बनाया जाये। दूसरा ये है कि गणेश गोदियाल की पीसीसी में वापसी हुई है ये हरीश रावत के लिए संतोषजनक हैं लेकिन पार्टी ने उन्हें फिलहाल प्रदेश में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। कैम्पेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह बनाये गये हैं और चुनाव समिति की कमान हरक सिंह रावत को सौंपी गयी है। करन माहरा को सेंट्रल वकिंग कमेटी में सदस्य बना दिया गया है। हालांकि पार्टियों की सभी बैठकों में उनका शामिल किया जाता रहा है। पदों की घोषणा के दौरान हरीश रावत ने शायद तंज करते हुए ये कहा था कि वो गणेश गोदियाल से आग्रह करेंगे कि उन्हें धर्मपुर विधानसभा में कहीं से बूथ अध्यक्ष बना दिया जाये ताकि वो अंतिम छोर की कमेटी को मजबूत करने की प्रेरणा दे सकें।

तीसरा हरीश रावत को एक पीड़ा जरूर है जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जाहिर करते रहते हैं। उनका मानना है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को कांग्रेस भुला चुकी है। 2014 और 2017 के बीच में जो उपलब्धियां उनकी सरकार ने हासिल की हैं, कांग्रेस किसी भी मंच पर उनकी चर्चा नहीं करती है। वो अकेले उन कार्यों पर बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो उपलब्धियां छोटी नहीं थीं। केदारनाथ पुर्ननिर्माण, गैरसैण में विधान भवन का निर्माण, ए.पी.एल कार्ड धारकों को राशन सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ हरीश रावत की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर या उनके बयानों में ही देखने को मिलते हैं। हरीश रावत की पीड़ा ये भी है कि 18 मार्च 2016 के घटनाक्रम को भी कांग्रेस भुला चुकी है। वो अक्सर कहते हैं कि

रावत की नहीं बल्कि कांग्रेस की जीत थी। एक सरकार सुप्रीम कोर्ट से जीती और उसी व्यक्ति को दुबारा मुख्यमंत्री बनाया गया ये आसान नहीं था।

हरीश रावत की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ है। वे आम जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और अक्सर लोगों से सीधे संवाद में विश्वास रखते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीजापुर गेस्ट हाउस में रात-दिन लोगों का तांता लगा रहता था। इस बीच उनकी ये कोशिश होती थी कि सबसे मुलाकात हो जाये और अब जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने वाले दूर-दराज से आते रहते हैं। कांग्रेस में एक बड़ा तबका आज भी हरीश रावत के पीछे है। जब उन्होंने राजनीतिक अवकाश की घोषणा की तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, ललित फर्सवाण और हरीश धामी खुलकर उनके समर्थन में आये। हरीश धामी ने तो सामने आकर हरक सिंह रावत पर भी कटाक्ष किये।

फिलहाल कांग्रेस के मंच पर हरीश रावत मौजूद नहीं हैं। यशपाल आर्य उनसे मुलाकात करने घर पर आ चुके हैं। गणेश गोदियाल उनसे फोन पर वार्ता कर चुके हैं। प्रीतम सिंह के साथ भी उनकी घंटों मुलाकात रही। संजय नेगी उनके घर पर आ चुके हैं और ये गुजारिश कर चुके हैं कि कम से कम मेरे लिए अवकाश ना ले और राजनीतिक सक्रियता जारी रखे। हरीश रावत राजनीतिक मौन हैं लेकिन सामाजिक आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। वो दूर से बैठकर राजनीति का आनन्द ले रहे हैं। अपने आलोचकों और प्रशंसकों की तुलनात्मक गणना कर रहे हैं। इस मौजूदा समय को सोशल मीडिया पर हरीश रावत अर्जित अवकाश का नाम दे रहे हैं और इस अर्जित अवकाश में उनकी राजनीतिक ताकत भी अर्जित हो रही है। समय तेजी से भाग रहा है। कांग्रेस को अपने आपसी मनमुटाव पर विचार तो करना होगा। 2027 करीब है। 10 साल सत्ता से दूरी हो जायेगी और हालात ऐसे ही रहे तो ये साल और बढ़ जायेंगे।

कार्यों से दूरी बनाने की बात कही है। उनका ये अवकाश उस समय जारी है जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी "नैलजा उत्तराखंड दौरे पर हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश में कांग्रेस के बड़े आयोजनों में मंच पर हरीश रावत मौजूद नहीं हैं।

हरीश रावत दशकों से उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, पक्ष में हो या विपक्ष में, हार या जीत हो, आलोचना हो या प्रशंसा हरीश रावत ने अपनी उपयोगिता को बनाये रखा है। वो खुद को चर्चाओं में रखना जानते हैं, वो मौन रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जानते हैं। इस बार भी उनका मौन कई शब्द बयां कर रहा है। क्या ये मौन महज एक व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने तक सीमित है? क्या ये मौन एक रामनगर सीट का झगड़ा हो सकता है? क्या पार्टी हरीश रावत को किनारे रखना चाहती है?

हरीश रावत के मुताबिक उनका 60 साल का राजनीतिक कार्यकाल हो चुका है। छत्र जीवन से ही वो राजनीति कर रहे हैं। हालांकि मुख्यधारा की राजनीति में भी उनको 46 साल हो चुके हैं। 1980 में पहली बार वो अल्मोड़ा से सांसद बने थे। ये उनका सौभाग्य रहा कि शुरूआत में ही देश के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर राजनीति में मजबूती के साथ

सिंह ऐरी और भाजपा के भगत सिंह कोशियारी उनके मुकाबले में हारे। 1991 में पहली बार हरीश रावत चुनाव हारे। भाजपा के प्रत्याशी जीवन शर्मा ने उन्हें हराया लेकिन फिर भी जीवन शर्मा से ज्यादा हरीश रावत चर्चाओं में रहे। आज जीवन शर्मा का नाम कोई भाजपा में भी नहीं लेता है। उस समय हरीश रावत के पास सेवादल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और अध्यक्ष स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस पद का लाभ हरीश रावत को मिला वो हारकर भी कमजोर नहीं हुए और राज्य आंदोलन में अपनी उपयोगिता साबित करते रहे। फिर लगातार दो बार वो बच्ची सिंह रावत से हारे लेकिन जमे रहे और राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने।

यहां से हरीश रावत का नया दौर शुरू हुआ। कांग्रेस जो प्रदेश में ना के बराबर थी। महज एक एमएलसी इंदिरा हृदयेश और तिवारी कांग्रेस से एक विधायक केसी बाबा थे। यहां से कांग्रेस 2002 में 36 सीटों तक पहुंची। इसमें हरीश रावत की मेहनत और कार्यशैली को दरकिनारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि पार्टी ने एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री पद सौंपा और पार्टी फोरम में हरीश रावत की अंदरूनी नाराजगी चलती रही। ये हरीश रावत की राजनीतिक कला है कि वो अनुशासन के दायरे में रूठना और अपनी

इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना पर समीक्षा बैठक हरिद्वार को मिलने जा रहा है आधुनिक रोपवे सिस्टम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में हरिद्वार को आधुनिक रोपवे सिस्टम मिलने जा रहा है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को राज्य सचिवालय में उत्तराखंड मेट्रो रेल

संचालन व्यवस्था की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से हरिद्वार शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने

प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है, वह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। इस पर सचिव आवास ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड शासन के सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तर



कॉर्पोरेशन द्वारा हरिद्वार शहर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन, लागत, भूमि हस्तांतरण, कन्सेशन अवधि और वित्तीय व्यवहार्यता समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव आवास ने अधिकारियों को परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।

बैठक के दौरान उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार मिश्रा ने हरिद्वार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का क्रियान्वयन और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत डीबीएफओटी आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण में परियोजना की संरचना, संभावित मार्ग, निर्माण कार्य और

में मदद मिलेगी।

समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने परियोजना की प्रति किलोमीटर लागत के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस पर प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि रोपवे स्टेशन, कार्यशाला और भूमि तथा अन्य आवश्यक क्लीयरेंस को छोड़कर परियोजना की संरचना के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग 75 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह लागत केवल निर्माण कार्य से संबंधित है, जबकि भूमि, स्टेशन निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं अलग से शामिल होंगी। बैठक में परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में रोपवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि

प्रदेश शासन को पुनः पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस विषय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है, इसलिए अब अनुस्मारक पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव सिंचाई, उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रस्तावित भूमि को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 99 वर्षों की लीज पर आवास विभाग, उत्तराखंड शासन को हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

समीक्षा के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को डीपीआर स्तर पर अनुमोदित करते हुए इसे आगे की कार्यवाही के लिए ईएफसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के सभी तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

प्रकृति के बीच सुकून भरा सफर देगा किपलिंग ट्रैक: बंशीधर तिवारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में राज्य में पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून से मसूरी को जोड़ने वाले ऐतिहासिक किपलिंग ट्रैक के पुनरोद्धार की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मसूरी

किपलिंग ट्रैक के विकास में केवल संरचनात्मक कार्य ही नहीं बल्कि पर्यटकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। परियोजना के अंतर्गत ट्रैक के विभिन्न स्थानों पर विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे, जहां आकर्षक गजीबो (बं. मड़व) बनाए जाएंगे। इन स्थानों पर



देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा लगभग 498.14 लाख रुपये की लागत से 3.50 किलोमीटर लंबे इस ऐतिहासिक ट्रैक का व्यापक विकास किया जा रहा है। यह ट्रैक शहनसाही आश्रम से झड़ीपानी तक फैला हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण तथा पहाड़ी दृश्यों के कारण लंबे समय से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आधुनिक सड़क मार्गों पर बढ़ती भीड़ और वाहनों के शोर के बीच यह ट्रैक एक ऐसे वैकल्पिक पर्यटन मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटक प्रकृति के करीब शांत और सुकून भरा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य सरकार की मंशा है कि मसूरी क्षेत्र में पर्यटन को केवल सड़क आधारित यात्रा तक सीमित न रखकर प्रकृति आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी सोच के साथ किपलिंग ट्रैक के संरक्षण और विकास की योजना तैयार की गई है, ताकि आने वाले समय में यह मार्ग पर्यटकों के लिए एक अनूठा और आकर्षक अनुभव बन सके।

एमडीडीए द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत ट्रैक के संरक्षण, मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर रिटैनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैक सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। साथ ही ट्रैक के किनारों पर मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी, ताकि पर्यटक सुरक्षित रूप से इस मार्ग पर भ्रमण कर सकें। इस मार्ग को पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए रास्ते को समतल और व्यवस्थित भी किया जाएगा।

पर्यटकों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

बैठकर पर्यटक आसपास के पर्वतीय दृश्यों, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैक पर सेल्फी प्वाइंट, कैंटीन कियोस्क, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शौचालय, कूड़ेदान और आधुनिक लैंप पोस्ट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इन व्यवस्थाओं से न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलेगी बल्कि ट्रैक को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान भी मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

इस परियोजना की खास बात यह है कि इसके विकास में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रैक के आसपास व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता और अधिक बढ़ेगी।

प्रकृति के बीच नया अनुभव देगा किपलिंग ट्रैक : बंशीधर तिवारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि किपलिंग ट्रैक का पुनरोद्धार राज्य के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश में ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर पर्यटकों को अलग अनुभव प्रदान करें। उन्होंने बताया कि देहरादून से मसूरी जाने वाले पारंपरिक सड़क मार्गों पर अक्सर भीड़भाड़ रहती है, जिससे पर्यटकों को शोर और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है।

किपलिंग ट्रैक के विकसित होने से पर्यटकों को एक वैकल्पिक और शांत मार्ग मिलेगा, जहां वे पैदल चलते हुए प्रकृति की गोद में समय बिता सकेंगे। बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस ट्रैक पर विकसित की जा रही सुविधाएं इसे एक सुरक्षित, आकर्षक और व्यवस्थित पर्यटन मार्ग के रूप में स्थापित करेंगी। यहां आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय दृश्यों और शांत वातावरण का आनंद लेते हुए एक अलग अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद यह ट्रैक न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक बेहतर मनोरंजन और प्रकृति से जुड़ने का स्थान बन जाएगा।

अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दून पुलिस ने चलाया अभियान

देहरादून। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं, कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में गौरा पुलिस की टीमों द्वारा स्कूल/कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों में छात्राओं, कामकाजी/ घरेलू महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गौरा पुलिस द्वारा उन्हें महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानून में किए गए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें महिलाओं की सहायता हेतु जारी किए गये महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 181 व अन्य आकस्मिक सहायता नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता के लिए विकसित किये गए 'गौरा शक्ति ऐप' की जानकारी देते हुए उसमें महिला सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें ऐप में शिकायत पंजीकरण, निकटतम



पुलिस स्टेशन/पिंक बूथ की जानकारी, महिला हेल्पलाइन 1091, 112 तथा महिला संबंधी कानूनों की सरल भाषा में जानकारी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा उनके मोबाइल फोन

पर ऐप डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। अभियान के दौरान सभी महिलाओं व छात्राओं द्वारा महिला सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।

ग्रामोत्थान परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित

चमोली। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक, ग्रामोत्थान श्री शशिकान्त यादव द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें अल्ट्रा पुअर पैकेज, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उद्यम,

आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उद्यम स्थापना तथा सहकारिताओं के माध्यम से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गठित सीएलएफ का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें और बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया

जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामोत्थान परियोजना एवं एनआरएलएम के बीच आपसी समन्वय (कन्वर्जेंस) के माध्यम से आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में परियोजना निदेशक श्री आनन्द सिंह सहित सभी विकासखण्डों के खण्ड विकास अधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक शशिकान्त यादव, सहायक प्रबंधक महेन्द्र कफोला, ग्रामोत्थान कार्मिक उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के लिए 75 दिनों की उलटी गिनती शुरू

स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार स्थित छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उद्यान में योग महोत्सव-2026 का आयोजन किया। इस आयोजन ने त्रिकोणासन करने वाले सबसे बड़े समूह के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने प्रातःकाल कॉमन योगा प्रोटोकॉल (सीवाईपी) का अभ्यास करने के लिए एकत्र होकर ऐतिहासिक शहर लोनार को सामूहिक कल्याण के एक जीवंत केंद्र में परिवर्तित कर दिया। इस व्यापक भागीदारी ने एकता, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति को उजागर किया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 75 दिन शेष रहने की एक सशक्त शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोनार क्षेत्र में इस आयोजन का होना समग्र स्वास्थ्य और सद्भाव की दिशा में एक व्यापक वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है। योग के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और भावनात्मक संतुलन को निरंतर बढ़ावा देता है। रिकॉर्ड तोड़ त्रिकोणासन प्रदर्शन के महत्व का उल्लेख करते हुए, श्री जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि योग में निहित सामूहिक भागीदारी और साझा कल्याण की भावना को दर्शाती है। उन्होंने आयुष आहार के महत्व को भी रेखांकित किया और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं समग्र स्वास्थ्य



को बढ़ावा देने में बाजरा, रागी, नारियल तेल और औषधीय मसालों जैसे पारंपरिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की भूमिका पर बल दिया। सभा को संबोधित करते हुए, आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दास ने योग को विश्व के लिए भारत के सबसे मूल्यवान योगदानों में से एक बताते हुए कहा कि यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में एमडीएनआईवाई के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) काशीनाथ समागंडी के नेतृत्व में कॉमन योगा प्रोटोकॉल का लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया।

सत्र में योगासन, प्राणायाम और ध्यान शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को योग के व्यापक लाभों का अनुभव करने का अवसर मिला। योग महोत्सव-2026 में आयुष मंत्रालय की कई प्रमुख पहलों को भी प्रदर्शित किया गया, जिनमें "हवाई यात्रा के लिए योग" प्रोटोकॉल, "गैर-संक्रामक रोगों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल" और दैनिक जीवन में योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गये योग जैसे 365 अभियान शामिल हैं। 14 दिनों के निःशुल्क निर्देशित योग

अभ्यास की सुविधा प्रदान करने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800-315-7008) को भी प्रमुखता से दिखाया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के लिए 75 दिनों की उलटी गिनती की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। पिछले ग्यारह संस्करणों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे बड़े वैश्विक आंदोलनों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ रही है। आगामी 12वें संस्करण में गैर-संक्रामक रोगों से निपटने, वृद्धावस्था स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को योग के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आयुष मंत्रालय ने जन भागीदारी के माध्यम से योग को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर में और विश्व स्तर पर व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।



नई दिल्ली। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने 6 अप्रैल, 2026 को रात 8:25 बजे सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकैलिटी (नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत) प्राप्त कर ली है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) द्वारा संयंत्र प्रणालियों की सुरक्षा की गहन समीक्षा के बाद जारी की गई मंजूरी के बाद प्राप्त की गई, जिसमें डीईई के सचिव और एईसी के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती, आईजीसीएआर के निदेशक श्री श्रीकुमार जी. पिल्लई, भाविनी के प्रभारी सीएमडी श्री अल्लू अनंत और भाविनी के पूर्व सीएमडी और होमी संथना अध्यक्ष श्री के.वी. सुरेश कुमार उपस्थित थे। पीएफबीआर की प्रौद्योगिकी का विकास और डिजाइन स्वदेशी रूप से इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) द्वारा किया गया था, जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है और इसका निर्माण और संचालन भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (भविनी) द्वारा किया गया था, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक थर्मल रिएक्टरों के विपरीत, पीएफबीआर यूरेनियम-प्लूटोनियम मिक्सड ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करता है। पीएफबीआर का कोर यूरेनियम-238 की परत से घिरा होता है। तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ यूरेनियम-238 को विखंडनीय प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करते हैं, जिससे रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर पाता है। रिएक्टर को अंततः परत में मौजूद थोरियम-232 का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूपांतरण के माध्यम से थोरियम-232 यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए ईंधन का काम करेगा।

यह अनुठी क्षमता परमाणु ईंधन संसाधनों के उपयोग को काफी हद तक बढ़ाती है और देश को अपने सीमित यूरेनियम भंडार से कहीं अधिक

क ऊर्जा निकालने में सक्षम बनाती है, साथ ही भविष्य में थोरियम के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए भी तैयारी करती है। प्रथम चरण की महत्वपूर्णता प्राप्त करने के साथ भारत अपने तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की पूर्ण क्षमता को साकार करने के करीब पहुंच गया है। फास्ट ब्रीडर तकनीक वर्तमान में मौजूद भारी जल रिएक्टरों और भविष्य में स्थापित होने वाले थोरियम-आधारित रिएक्टरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है, जिससे देश के प्रचुर थोरियम संसाधनों का लाभ उठाकर दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। इस उपलब्धि से भारत के स्वदेशी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण तंत्र की मजबूती का पता चलता है। इस रिएक्टर में उन्नत सुरक्षा प्रणालियां, उच्च तापमान वाले तरल सोडियम शीतलक की तकनीक और एक बंद ईंधन चक्र दृष्टिकोण शामिल है, जो परमाणु सामग्रियों के पुनर्चक्रण को सक्षम बनाता है, जिससे स्थिरता में सुधार होता है और अपशिष्ट कम होता है। यह परियोजना उन असंख्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और उद्योग भागीदारों के समर्पण को भी दर्शाती है, जिन्होंने मुख्यतः स्वदेशी तकनीकों और घटकों का उपयोग करते हुए रिएक्टर के डिजाइन, निर्माण और संरचना में योगदान दिया है।

उनके प्रयासों से उन्नत परमाणु अभियांत्रिकी में राष्ट्र की बढ़ती क्षमता उजागर होती है और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

ऊर्जा उत्पादन के अलावा, फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम परमाणु ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों, उन्नत सामग्रियों, रिएक्टर भौतिकी और बड़े पैमाने की इंजीनियरिंग में रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करता है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से विकसित ज्ञान और बुनियादी ढांचा भविष्य के रिएक्टर डिजाइनों और अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकियों का समर्थन करेगा। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने विस्तार को जारी रखते हुए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उच्च तापीय दक्षता के साथ विश्वसनीय, कम कार्बन उत्सर्जन वाली और आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रथम क्रिटिकैलिटी का प्राप्त होना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि विकसित भारत के लिए एक सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।

एआई-संचालित बहुभाषी संवाद मंच बाँब संवाद का शुभारंभ

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग सचिव श्री एम. नागराजू ने मुंबई में औपचारिक तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बाँब संवाद आरंभ किया। यह प्लेटफॉर्म एआई-संचालित बहुभाषी विशिष्ट संवाद मंच है, जिसका उद्देश्य शाखाओं में ग्राहकों के साथ संवाद बेहतर बनाना है। पहली बार किसी बैंक ने इस तरह का प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। भाषा संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए तैयार किये गये इस प्लेटफॉर्म से ग्राहकों और बैंक शाखा के कर्मचारियों को पसंदीदा भाषा में एक-दूसरे के साथ सहजता से संवाद करने में सुगमता होगी। श्री एम. नागराजू ने यह पहल आरंभ करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा को बधाई दी। उन्होंने बैंक के कार्यों में भाषाई बाधा दूर करने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अभिनव प्रौद्योगिकी प्रयोग की सराहना की। वित्तीय सेवा विभाग सचिव ने कहा कि बाँब संवाद अधिक समावेशी और सुलभ सेवा को बढ़ावा देगा और बैंक शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार में सहायक

होगा। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पहल ने इस क्षेत्र में नया मानदंड स्थापित किया है। श्री नागराजू ने बैंक की एक और हरित पहल बाँब फॉरेस्ट का भी दौरा किया, जो बाँब अर्थ, ग्रीन डिपॉजिट्स और ग्रीन बॉन्ड्स के बाद स्थापित किया गया है और संधारणीयता और पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी समग्र लक्ष्य के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बाँब फॉरेस्ट मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के बीकेसी कार्यालय में बनाया गया 6,000 वर्ग फुट का हरित उद्यान है जो जैव विविधता और स्वच्छ हवा प्रदान करता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देवदास चंद ने इस पहल पर कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा बाँब संवाद द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से अपनी शाखाओं को अधिक समावेशी और ग्राहक-अनुकूल बना रहा है, जिससे स्थानीय भाषाओं और वास्तविक समय में ग्राहकों के साथ संवाद हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रौद्योगिकी को ग्राहक-केंद्रित डिजाइन के साथ युक्त कर

कामकाज बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पूर्णतया स्वविकसित बाँब संवाद एआई-संचालित संभाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों के उपयोग से 22 भाषाओं में वास्तविक समय में, कम विलंबता से दो-तरफा संचार सुगम बनाता है। इससे प्रसंग सटीकता और प्राकृतिक प्रवाह के साथ ही भारत की भाषाई विविधता भी सुनिश्चित होगी। सेवा काउंटर पर, इस एप से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले ग्राहकों और शाखा कर्मचारियों के बीच निर्बाध संचार सक्षम होगा।

ग्राहक की पसंदीदा भाषा या प्रश्न का कर्मचारी तुरंत अनुवाद कर पाएंगे और उनकी बात भी ग्राहक अपनी भाषा में समझ लेंगे। इससे वास्तविक समय में सहज बातचीत संभव होगी, जिससे कार्यों की सटीक समझ और कुशल सेवा प्रदान होगी। इस प्रणाली में बातचीत स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित होती है, साथ ही एक वैकल्पिक वॉइस मोड भी है जो टेक्स्ट को स्पीच में बदल देता है